Election Commission of India

28

NAME OF THE NEWSPAPER THE TIMES OF INDIA DATE: 13 JUN 2012

Under Fire

Severe test for Congress in Andhra bypolls

Yesterday's byelections to 18 assembly constituencies and one Lok Sabha seat in Andhra Pradesh are expected to have crucial implications for multiple political stakeholders at state and central levels. Both Congress and its usual political adversary, the Telugu Desam Party, are under threat from a resurgent YSR Congress, led by Jagan Mohan Reddy. It's also to be seen whether the regional Praja Rajyam Party, founded by actor Chiranjeevi and which merged with the Congress last year, is able to add to the Congress's vote share.

Dramatic scenes had unfolded in the run-up to the bypolls, culminating in the CBI's arrest of Jagan in a disproportionate assets case just on the poll eve. If Jagan sweeps the polls, as many are expecting, the jury will be out on whether his arrest drew sympathy to him as Y S Rajasekhara Reddy's 'victimised' legatee, or whether his victory was a foregone conclusion anyway because of YSR's popularity in the state. The bypoll results, expected later this week, could change the complexion of Andhra's political dynamic, and set the backdrop for general as well as assembly elections two years from now. A victory for YSR Congress could wrest from the Congress a chunk of the 156 seats and 42 constituencies that the latter had won respectively in the 2009 assembly and Lok Sabha elections. Congress will have few takers in the Telangana region as well, after first promising to fulfil and then going back on the demand for a separate state there. If Congress's Andhra bastion falls, it will have difficulty making up that loss elsewhere in the country.

NAME OF THE NEWSPAPER राजस्थान पत्रिका DATE: 13 JUN 2012

न हो कड़वाहट

सम्पादकीय

राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही देश को अब सत्तारूढ़ यूपीए की तरफ से उम्मीदवार के नाम का इंतजार है। विचार-विमर्श की प्रक्रिया अंतिम दौर में है, लिहाजा माना जा सकता है कि देश के भावी राष्ट्रपति का नाम शीघ्र सामने आ जाएगा। वोटों के अंकगणित पर नजर डाली जाए, तो साफ हो जाएगा कि इस बार चुनाव निर्विरोध होने के प्रबल आसार हैं। लगभग ग्यारह लाख वोटों के निर्वाचन मण्डल में यूपीए के पास साढ़े चार लाख मत हैं, तो प्रमुख विपक्षी गठबंधन एनडीए के खाते में मात्र तीन लाख वोट ही हैं। सरकार को समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल के मतों को भी मिला लिया जाए, तो यूपीए का आंकड़ा जीत के पार पहुंच जाता है। ऐसे में यूपीए के प्रत्याशी को भावी राष्ट्रपति मान लेने में शायद ही किसी को संकोच हो। राष्ट्रपति पद के लिए हुए पिछले चुनाव में एनडीए जरूर सक्रिय था और उसने अपना प्रत्याशी मैदान में भी उतारा था, लेकिन इस बार एनडीए खेमे की खामोशी को देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव महज औपचारिकता भर होगा। एनडीए ने भी मान लिया है कि चुनाव में उतरना औपचारिकता निभाना भर ही होगी। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष रहे पी.ए. संगमा जरूर राजनीतिक दलों से समर्थन मांगकर चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं, लेकिन लगता नहीं है कि उन्हें समर्थन मिल पाएगा। यूपीए और एनडीए खेमों के बीच मतों का अंतर जब डेढ़ लाख हो, तो मुकाबले की बजाय सर्वसम्मति से चुनाव कराना ही राजनीतिक दलों के साथ देशहित में भी होगा। पिछली बार यूपीए की प्रतिभा पाटिल और एनडीए के उम्मीदवार भैरोंसिंह शेखावत के बीच प्रचार अभियान के दौरान उपजी कड़वाहट को देश देख चुका है। उम्मीद है कि वैसी परिस्थितियां फिर पैदा न हों।

> इस बार राष्ट्रपति चुनाव सहमति से ही होना चाहिए, पिछली बार की तरह तनाव पैदा करना कदापि ठीक नहीं होगा।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बुधवार को यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी से संभावित मुलाकात के बाद प्रत्याशी चयन का मामला सुलझने के पूरे आसार हैं। देश में अधिकांश मौकों पर राष्ट्रपति चुनाव सर्वसम्मति से होता आया है। राजनीतिक दलों के बीच तमाम मतभेदों और टकराहट के बावजूद राष्ट्रपति-उप राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में सर्वसम्मति बनाने पर सहमति हो ही जानी चाहिए। आखिर में तो दोनों पद संवैधानिक ही हैं और उसी अनुरूप राजनीतिक दलों को इनका सम्मान भी करना चाहिए। मतभेद राजनीतिक मुद्दों तक ही सीमित रहें, तो बेहतर है। कुछ मुद्दों पर सहमति की इन्हीं कवायदों से लोकतंत्र और मजबूत होता है, इसे भी मानना होगा।